

# आंध्रप्रदेश में मुसलमानों को आरक्षण का मुद्दा

### प्रलिम्सि के लियै:

आरक्षण, <u>इंद्रा साहनी नरि्णय,</u> अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 16(4A), अनुच्छेद 16(4B), अनुच्छेद 15(4)

### मेन्स के लिये:

सार्वजनकि रोज़गार और संबंधति निर्णयों में **आरक्षण**, धर्म के आधार पर आरक्षण

सरोत: इंडयिन एकसपरेस

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में वर्ष 2004 में आंध्रप्रदेश में मुसलमानों को प्रदत्त 5% आरक्षण का मुद्दा पुनः चर्<mark>चा में है</mark>, जि<mark>ससे धर्म-आधार</mark>ति आरक्षण से संबंधति बहस दोबारा शुरू हो गई है।

## आंध्रप्रदेश में मुसलमानों को आरक्षण की पृष्ठभूमिः

#### • परचिय:

- आंध्रप्रदेश में, जहाँ मुसलमानों की आबादी लगभग 9.5% है, जबकि कुछ मुस्लिम समूह पूर्व से ह<u>ी राज्य ओ.बी.सी. अनुसूची</u> में शामिल हैं, जिसमें उन्हें 7% से 10% तक का आरक्षण कोटा प्राप्त है।
  - हालाँकि, कर्नाटक और केरल के मॉडल का अनुसरण करते हुए सभी मुसलमानों को अन्य पछिडा वर्ग की श्रेणी में शामिल करने पर ज़ोर दिया गया है।

#### वर्ष 2004 में आरक्षण:

- ॰ जून, 2004 में सरकार ने OBC सूची में शामिल करने के लिये राज्य में मुसलमानों की **सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति** की जाँच की, जिसके परिणामस्वरूप <mark>अनुचछेद 15(4) और 16(4)</mark> के तहत 5% **आरक्षण** दिया गया।
- ॰ हालाँकि, आंध्रप्रदेश उँच्च न्यायालय ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संदर्भित किये बिना क्रीमी लेयर को आरक्षण की श्रेणी से बाहर न करने के लिये लागू किये जाने वाले आरक्षण कोटा को रद्द कर दिया था।
  - न्यायालय ने कहा कि मुस्लिम समुदाय को एक समान समूह (Homogenous Group) नहीं माना जा सकता है।
  - न्यायालय के समक्ष प्रमुख प्रश्नों में से एक यह था कि क्या एक समूह के रूप में मुसलमान संवैधानिक ढाँचे के भीत सकारात्मक कार्रवाई के हकदार हैं, जिस पर न्यायालय ने ने सकारात्मक कार्रवाई के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए कहा कि इस तरह के आरक्षण धर्मनिरिपेक्षता का उल्लंघन नहीं करते हैं।

#### वर्ष 2005 में आरक्षण:

- ॰ **पछिड़ा वर्ग आयोग** ने **समस्त मुस्लिम समुदाय** को सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पछिड़ा बताते हुए आरक्षण देने की सिफारिश की।
- ॰ राज्य सरकार ने फरि से मुसलमानों को 5% कोटा देने वाला एक <mark>अध्यादेश</mark> पेश किया, जिसे बाद में कानून से बदल दिया गया।
- ॰ उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए कि आयोग ने यह निष्कर्ष निकालने के लिये वस्तुनिष्ठ मानदंडों (एम. नागराज बनाम भारत संघ, 2006) पर भरोसा नहीं किया कि एक समूह के रूप में मुस्लिम आंध्र प्रदेश में पिछड़े थे, एक बार फिर कोटा को रदद कर दिया गया।
- ॰ इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसने वर्ष 2010 में मामले की सुनवाई होने तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया।

#### वर्तमान स्थितिः

- ॰ सर्वोच्च न्यायालय में अंतिम सुनवाई वर्ष 2022 के लिये निर्धारित की गई थी। हालाँकि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) कोटा मुद्दे पर निर्णय होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई करने का निर्णय किया।
- EWS कोटा नवंबर, 2022 में मंज़ूरी दे दी गई थी, लेकिन AP कोटा मुद्दे पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है।

#### आंध्र के आरक्षण मॉडल से जुड़े मुद्दे:

• मुसलमानों को एक समरूप समूह मानना **संवधान की मूल संरचना** में समानता के सदिधांत का उल्लंघन है।

- ॰ यह केवल धर्म के आधार पर आरक्षण देने पर संवैधानिक निषध का भी उल्लंघन करता है (अनुच्छेद 15(1) और 16(2))।
- उच्च न्यायालय ने पाया कि आंध्र प्रदेश की आरक्षण सीमा (46%) अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत प्रदत्त कोटा के अनुरूप है और इसमें मुसलमानों के लिये 5% आरक्षण देने से 50% की सीमा का उल्लंघन होता है, इस उल्लंघन के लिये बाध्यकारी कारणों की कमी पर प्रश्न उठाया।

### अन्य राज्यों में समान धर्म आधारति आरक्षण:

- केरल: अपने 30% OBC कोटा के भीतर 8% मुस्लिम कोटा प्रदान करता है।
- तमिलनाडु और बिहार: अपने OBC कोटे में मुस्लिम जाति समूहों को भी शामिल करते हैं।
- कर्नाटक: 32% OBC कोटा के अंतर्गत मुसलमानों के लिये 4% उप-कोटा निर्धारित था।
  - ॰ राज्य सरकार ने वर्ष 2023 में इस उप-कोटा को वोक्कालिंग और लिंगियतों के बीच पुनर्वतिरित किया।
- कर्नाटक का हालिया मुद्दा:
  - राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) ने कर्नाटक में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) कोटा के वर्गीकरण के संबंध में, विशेष रूप सेश्रेणी II-B के तहत मुसलमानों के लिये "ब्लैंकेट रिज़र्वेशन" के मुद्दे को संबोधित करते हुए, कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव को समन किया है।
  - ॰ **वर्तमान स्थिति:** कर्नाटक OBC वर्गीकरण की **श्रेणी II-B** के तहत मुसलमानों को वर्गीकृत करता है, इसके अलावा **श्रेणी I** में 17 और **श्रेणी II-A** में 19 मुस्लिम जातियाँ शामिल हैं।
  - NCBC की चिता:
    - NCBC मुसलमानों के लिये एक पृथक श्रेणी की आवश्यकता पर प्रश्न उठाती है और उनके पिछड़े वर्गीकरण को उचित ठहराने वाली रिपोर्टों की वैधता पर संदेह करती है।
    - NCBC का दावा है कि OBC कोटा के भीतर वर्गीकरण के कारणकर्नाटक में मुसलमानों को स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश में विशेष परतिनिधितव दिया जा रहा है।
    - NCBC को चिता है कि **सभी मुसलमानों को <u>सथानीय निकाय</u> चुनावों में किसी भी OBC या सामान्य श्रेणी की सीट से चुनाव लड़ने की अनुमति देने** से अन्य योग्य OBC समुदाय अवसरों से वंचित हो सकते हैं।
  - · कर्नाटक सरकार का तर्क:
    - कर्नाटक सरकार ने विभिन्न राज्य आयोगों द्वारा अनुशंसित मुसलमानों को न तो जाति और न ही धर्म, बल्कि पिछिड़ा वर्ग मानते हुए श्रेणी II-बी के तहत वर्गीकृत को उचित ठहराया।

## आरक्षण से संबंधति वभिनि्न कानूनी प्रावधान क्या हैं?

- संवैधानिक प्रावधान:
  - ॰ **संवधिान का अनुच्छेद 16(4)** "पछिड़े वर्ग के नागरिकों" के लिये आरक्षण की अनुमति देता है। **राज्यों** को यह निर्धारित करने का **विवेक** है कि किनि समुदायों को पछिड़े वर्गों के रूप में रखा जा सकता है।
    - अनुच्छंद 15 के तहत शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिये अर्हता प्राप्त करने के लिये, एक समूह कोपहले अपना सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन प्रदर्शित करना होगा तथा अनुच्छंद 16(4) के तहत सार्वजनिक रोज़गार में आरक्षण के लिये अधिकारियों को समूह के पिछड़ेपन और सार्वजानिक रोज़गार में इसके अपर्याप्त प्रतिनिधित्व दोनों को सुनिश्चित करना होगा।
- सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णय:
  - · चंपकम दोरायराजन बनाम मदरास राज्य (वर्ष 1951):
    - शैक्षिक संस्थानों में केवल जाति के आधार पर आरक्षण को समापत कर दिया।
    - संविधान के प्रथम संशोधन का नेतृत्त्व किया।
  - इंदरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ, 1992:
    - आरक्षण पर परिभाषित सीमाएँ:
      - क्रीमी लेयर का बहिष्कार
      - 50% कोटा सीमा
      - ॰ पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं (एससी/एसटी को छोड़कर)।
  - ॰ एम. नागराज बनाम भारत संघ मामला, 2006:
    - अनुच्छेद 16 को बरकरार रखा (4A पदोन्नति में एससी/एसटी के लिये आरक्षण की अनुमति देता है)
    - ऐसी नीतियों के लिये 3 शर्ते स्थापित की गईं:
      - ॰ सामाजिक एवं शैक्षणिक पछिड़ापन
      - अपर्याप्त प्रतिधित्व
      - ॰ दक्षता को बनाए रखना
  - जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता मामला, 2018:
    - SC एवं ST के लिये पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति
    - राज्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पिछड़ेपन पर मात्रात्मक डेटा एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है।
  - जनहति अभियान बनाम भारत संघ, 2022:
    - सर्वोच्च न्यायालय ने 103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखा है जो पूरे भारत में सरकारी नौकरियों और कॉलेजों में अगड़ी जातियों के बीच आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (Economically Weaker Sections - EWS) के लिये 10%

# भारत में धर्म-आधारति आरक्षण से संबंधति तर्क क्या हैं?

- भारत में धर्म-आधारित आरक्षण के पक्ष में तर्क:
  - ॰ **सामाजिक-आर्थिक पछिड़ापन: सच्चर समिति की रिपोर्ट के अनुसार**, भारत में मुसलमान शिक्षा, रोज़गार और आय जैसे <mark>सामाजिक-आरथिक असमानता</mark> के मामले में अन्य समुदायों से पीछे हैं।
    - आरक्षण इस अंतर को कम करने में सहायता कर सकता है।
  - **संवैधानिक आदेश:** भारतीय संविधान **धार्मिक** और सांस्कृतिक संप्रदाय के बावजूद सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिये सकारात्मक कार्रवाई का प्रावधान करता है।
  - ॰ **पर्याप्त प्रतिनिधितिव सुनश्चिति करना:** आरक्षण रोज़गार, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में कम प्रतिनिधितिव वाले धार्मिक समूहों का पर्याप्त प्रतिनिधितिव सुनश्चिति कर सकता है।
- भारत में धर्म-आधारति आरक्षण के विरुद्ध तर्कः
  - धर्मनरिपेक्षता: आलोचकों का तर्क है कि धर्म के आधार पर आरक्षण प्रदान करनाभारतीय संवधान में निहित धर्मनरिपेक्षता के सिद्धांत के विरुद्ध है, जो राज्य दवारा सभी धरमों के साथ समान वयवहार की वकालत करता है।
  - राष्ट्रीय एकता को कमज़ोर करना: धर्म-आधारित आरक्षण राष्ट्रीय एकता को कमज़ोर कर सकता है क्योंकि इससे विभिन्निसमुदायों के बीच वैचारिक विभाजन हो सकता है।
  - ॰ **आर्थिक मानदंड:** आरक्षण केवल धर्म के स्थान पर आर्थिक मानदंडों पर आधारित होना चाहिय, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ उन लोगों तक पहुँचे जो वास्तव में आर्थिक रूप से वंचित हैं, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो।
  - ॰ **प्रशासनकि चुनौतियाँ:** धर्म के आधार पर आरक्षण लागू करने से **प्रशासनकि चुनौतियाँ** उत्पन्न हो <mark>सक</mark>ती हैं, जैसे लाभार्थियों की पहचान के लिये **मानदंड निर्धारित करना** एवं प्रणाली के दुरुपयोग को रोकना।

#### आगे की राह

- सामाजिक-आर्थिक मानदंड: धर्म के स्थान पर आरक्षण सामाजिक-आर्थिक मानदंडों पर आधारित हो सकता है, जिससे यह सुनिश्चित किया
  जा सके कि लाभ सबसे वंचित व्यक्तियों तक पहुँचे, यद्यपि उनका धर्म कुछ भी हो।
- शिक्षा के माध्यम से सशक्तीकरण: पिछड़े समुदायों को सशक्त बनाने और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लियेशैक्षिक बुनियादी ढाँचे में सुधार के साथ-साथ कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना।
- समावेशी नीतियाँ: धर्म आधारित आरक्षण का सहारा लिये बिना, शिक्षा, रोज़गार एवं स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्रों में पिछड़े धार्मिक समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करने वाली समावेशी नीतियों को लागू करना।
- संवाद एवं सर्वसम्मति: विभिन्न समुदाय, उनके सामने आने वाली सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने के लिये आम सहमति पर पहुँचने के लिये सभी हितधारकों को शामिल करते हुए संवाद में शामिल हों, यह सुनिश्चित करते हुए कि उठाए गए कोई भी उपाय संवैधानिक मूल्यों एवं सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

#### दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण प्रदान करने की संवैधानिक वैधता एवं सामाजिक-राजनीतिक निहितार्थों पर चर्चा कीजिये । यह धर्मनिरपेक्षता, समानता एवं सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को किस प्रकार से प्रभावित करता है?

### UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

#### [?]?]?]?]?]?]?]:

प्रश्न. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अवधि के नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखिति में से किसकी अनुशंसा की गई थी/थीं? (2011)

- 1. भारत के लिये पूरण स्वतंत्रता।
- 2. अल्पसंख्यकों की सीटों के आरक्षण के लिये संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र।
- 3. संवधान में भारत के लोगों के लिय मौलिक अधिकारों का प्रावधान

#### नीचे दिये गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिय:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

### ?!?!?!?!:

प्रश्न. क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिये संवैधानिक आरक्षण के क्रियान्वयन का प्रवर्तन करा सकता है? परीक्षण कीजिये। (2018)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/issue-of-reservation-for-muslims-in-andhra-pradesh

